2019 में चिंताओं के साथ उम्मीद की किरणें

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक- सी. रंगराजन (पूर्व गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक)

04 जनवरी, 2019

"यदि भारत को उच्च विकास दर हासिल करनी है, तो पाँच मुद्दों को बड़े पैमाने पर संबोधित करने की आवश्यकता है।"

चाहे जो भी स्थिति पिछले वर्ष में रही हो, नए साल को हमेशा आशा भरी नजरों से ही देखा जाता है और भारत के लिए वर्ष 2018 वैश्विक और घरेलू स्तर पर मिश्रित फल देने वाला रहा है।

विश्व स्तर पर, 2018 में विकास दर उच्च थी, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन, हमें व्यापार युद्ध का एक मजबूत संकेत भी देखने को मिला है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तेजी से बढ़ने की उम्मीदें धीमी पड़ गईं। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग होने की पीड़ा से गुजर रहा है। इसके अलावा, घरेलू स्तर पर, पहली तिमाही की वृद्धि दर अधिक तो थी, लेकिन साल के अंत में एक संतुलन के रूप में संकेत अच्छे नहीं मिले हैं।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रुपये में गिरावट आई, लेकिन तेल की कीमतों में गिरावट के बाद यह थोड़ा सा संभल गया। इसके साथ ही जब कीमतें गिरीं, तो कृषि संकट बढ़ गया, यानि कुल मिलाकर समस्या कायम रही।

देखा जाये तो वर्ष 2018-19 में भारत की विकास दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 7.4% पर अनुमानित है। लेकिन यह एक टच-एंड-गो वाली स्थिति है। यहाँ कम रहने की संभावना अधिक है। आगे की ओर देखें तो 2019 में विकास दर में कोई खास बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। भले ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्थिर हो गया हो, लेकिन बहुत कुछ निवेश दर में बढ़ोतरी पर निर्भर करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय वातावरण हमारे विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है; इससे हमारे निर्यात और विकास पर प्रभाव पड़ेगा। जिसके कारण, शायद विकास दर 7.2% और 7.5% के बीच ही रहे। हालांकि यह किसी भी देश की उच्चतम विकास दर हो सकती है, लेकिन यह हमारी आवश्यकताओं से कम है।

अब इस आलेख में हम जानेंगे कि हमारी यानि कि भारत कि प्रमुख चिंताएं क्या हैं?

निवेश अनुपात

अंतिम विश्लेषण में, विकास दर निवेश की दर और पूंजी की उत्पादकता या इसके उलट वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात पर निर्भर करती है।

वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात सभी का सम्मिलित रूप है। यह श्रम की गुणवत्ता जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है, जो फिर से शिक्षा और कौशल विकास के स्तर और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है और यह लगातार बदल रहा है। निरंतर उच्च विकास सुनिश्चित करने के लिए, हमें निवेश अनुपात बढ़ाने और वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात को 4 पर रखने की आवश्यकता है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण अनुपात 2007-08 में 35.8% से गिरकर 2017-18 में 28.5% हो गया है।

निवेश अनुपात बढ़ाने की यात्रा आसान नहीं होने वाली है। हमे एनिमल स्पिरिट्स (Animal Spirits, यह एक शब्द है जो एक बाजार अर्थव्यवस्था में निवेशकों और उपभोक्ताओं के व्यवहार को निर्देशित करने वाली भावनाओं और प्रवृत्ति को संदर्भित करता है) को पुनर्जीवित करना चाहिए। एक शांत राजनीतिक और आर्थिक वातावरण को पोषित करने की आवश्यकता है।

बैंकिंग प्रणाली

आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक हमारी बैंकिंग प्रणाली की स्थिति है। मार्च, 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋणों के अनुपात के रूप में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए), 16.7% के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण के अनुपात में थीं। 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) के तहत हैं। यह इन बैंकों की ऋण देने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है। इसके साथ, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) प्रणाली भी तनावग्रस्त है।

यह आंशिक रूप से बैंकिंग प्रणाली में तनाव का प्रतिबिंब है क्योंकि अधिकांश एनबीएफसी बैंकों से उधार लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण आंशिक रूप से समस्या का समाधान करेगा। यह इस बिंदु पर स्पष्ट नहीं है कि यह ऋण देने की क्षमता को जोड़ने में कितना मद्द करेगा।

कुछ लोगों ने पीसीए ढांचे के बाहर बैंकों को अधिक पूंजी प्रदान करने की वकालत की है, क्योंकि इससे उनकी ऋण देने की क्षमता तुरंत बढ़ जाएगी।

आज, बैंक अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधार दोनों के लिए जिम्मेदार हैं। उधार देने में उनकी अक्षमता कार्यशील पूंजी की उपलब्धता के साथ-साथ पूंजीगत व्यय को भी प्रभावित करती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिक पूंजी प्रवाह बढाने का निर्णय जल्द पूरा किया जाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में विकास दर इस बात पर निर्भर करेगी कि बैंकिंग प्रणाली कितनी जल्दी सामान्य स्थिति में वापस आती है।

रोजगार वृद्धि

रोजगार की अपर्याप्त वृद्धि के बारे में एक बड़ी चिंता है। ईमानदारी से, हमारे पास संतोषजनक रोजगार संख्या नहीं है। संगठित क्षेत्र में रोजगार के आंकड़े विश्वसनीय हैं। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार बहुत बड़ा है। एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता रहा है कि यदि विकास 7% के आसपास है, तो रोजगार में कोई एकसमान वृद्धि क्यों नहीं है? हमें दो कारकों को ध्यान में रखना होगा।

विकास या तो निवेश में वृद्धि के कारण या मौजूदा क्षमता के बेहतर उपयोग के कारण हो सकता है। यह विकास है जो नए निवेश का नेतृत्व करता है जिससे रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। लेकिन मौजूदा पूंजी के उपयोग की बेहतर दक्षता के कारण विकास से रोजगार में मामूली वृद्धि हो सकती है।

दूसरा, 2004-05 और 2009-10 के बीच की अवधि में रोजगार में वृद्धि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय क्षेत्रों की तेजी से वृद्धि के कारण हुई है। आईटी सेक्टर धीमा हो गया है। वित्तीय क्षेत्र तनाव में है। इन क्षेत्रों में रोजगार दिखाई दे रहा था और श्रम बाजार में शिक्षित प्रवेशकों को पर्याप्त अवसर भी मिले थे। आईटी क्षेत्र की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना नहीं है क्योंकि यह उद्योग कई संरचनात्मक परिवर्तनों से गुजर रहा है। बैंकिंग प्रणाली का पुनरुद्धार कई कारकों पर निर्भर करता है।

भारत का बाहरी क्षेत्र बड़ा हो गया है और बाकी दुनिया के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वस्तुओं और सेवाओं में भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद का 42% हो गया है। इसलिए, बाकी दुनिया में जो होता है, वह भारत के विकास को बहुत प्रभावित करता है। उदारीकरण के बाद से भारत की भुगतान की स्थिति आरामदायक है। लकिन इसके बावजूद, 2018 के सितंबर-अक्टूबर में हमें इसमें कई कमजोरियां देखने को मिली हैं, जब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रुपये का मूल्य अचानक गिर गया था और पूंजी के बहिर्वाह भी थे।

आरबीआई के हस्तक्षेप और क्रूड की कीमतों में बाद की गिरावट ने रुपये के मूल्य की स्थिति को थोड़ा बेहतर किया। अप्रैल-नवंबर 2018 में, भारत के वस्तुओं का निर्यात 11.6% बढ़ा है। हालाँकि, हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि निर्यात वृद्धि 5.2% (2016-17) और 9.8% (2017-18) थी। निर्यात में मजबूत वृद्धि रखने के लिए हमें चालू खाते के घाटे (सीएडी) को प्रबंधनीय स्तर पर रखना होगा।

विश्व व्यापार और उत्पादन के लिए पूर्वानुमान उत्साहजनक नहीं है। यहाँ बहुत सी अनिश्चितताएं हैं, जिसमें ट्रेड वार में आई तीव्रता शामिल है। निर्यात प्रोत्साहन के साथ, हमें अपने कुछ बड़े आयातों को भी समाहित करने की आवश्यकता है। अगर हमें स्थिरता के साथ विकास हासिल करना है तो भारत की सीएडी पर एक नजर रखना महत्वपूर्ण साबित होगा।

कृषि संकट

भविष्य की वृद्धि कृषि के प्रदर्शन पर भी निर्भर करती है। कृषि संकट व्यापक है। अजीब बात है कि कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट एक मायने में उत्पादन बढ़ाने में हमारी सफलता का प्रतिबिंब है। कुछ साल पहले, हमारे लिए चिंता का विषय दालों की कीमत में असामान्य रूप से उच्च स्तर की वृद्धि थी। लेकिन आज स्थिति बिलकुल उलट है। शुक्र है कि उत्पादन में वृद्धि हुई और कीमतें गिर गई, नहीं तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती। सब्जियों के संबंध में भी ऐसा ही है, खासकर प्याज का। कृषकों की आवश्यकता वर्तमान कीमतों में आमदनी होना है।

कीमतों में गिरावट का समाधान बाजार में सरकार के हस्तक्षेप और सामान्य स्तर पर अधिशेष खरीदने से है। इसके बाद बाजार स्वचालित रूप से कीमतों को सामान्य स्तर पर ले जाएगा। इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण आवश्यकता केवल खरीद करने के लिए सरकार की वित्तीय क्षमता नहीं है, बल्कि खरीद और भंडारण के लिए पर्याप्त शारीरिक व्यवस्था भी है। खरीदे गए कृषि उत्पादों को सरकार द्वारा बाद के वर्षों में बेचा जा सकता है जब उत्पादन कम हो या इसे किसी भी सुरक्षा कार्यक्रम में उपयोग किया जाता है।

ऋण छूट सबसे अच्छा अल्पकालिक समाधानों में से एक हैं। बुनियादी समस्या उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को बढ़ी हुई उत्पादन और बेहतर कीमतों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने में से एक है। यहाँ एक बुनियादी कमजोरी भी है जिसे हमें संबोधित करना होगा। भूस्वामियों का औसत आकार इतना छोटा है कि उत्पादकता में कोई भी वृद्धि पर्याप्त आय नहीं दे पाती है।

किसानों को लैंडहोल्डिंग के समेकन के संदर्भ में सोचना होगा ताकि उन्हें बड़े आकार का लाभ मिल सके। छोटे किसानों को भी सब्जियों जैसे उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों के बारे में सोचना होगा। उत्पादकता बढ़ाने, भूस्वामियों को मजबूत करने और बेहतर आय के किसानों को आश्वस्त करने के लिए विपणन में सुधार के लिए एक संयुक्त हमले की आवश्यकता है।

हमारे पास पाँच चिंताएँ हैं जिसके साथ हम वर्ष 2019 में प्रवेश कर चुके हैं। ये हैं: निवेश अनुपात को बढ़ाना, बैंकिंग प्रणाली को पटरी पर लाना, बेहतर विकास के माध्यम से रोजगार का सृजन, सीएडी को शामिल करने के लिए निर्यात वृद्धि को बढ़ाना और उत्पादकता में वृद्धि और छोटे भूस्वामियों के समेकन से कृषकों के संकट को दूर किया जाना। यदि हमें निरंतर उच्च विकास हासिल करना है तो इन मुद्दों को बड़े पैमाने पर संबोधित करने की आवश्यकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ

परिचय

- पिछले वर्ष विमुद्रीकरण, मौद्रिक नीति का नया ढाँचा, मुद्रास्फीति नियोजन, वित्तीय संघवाद और बाहरी क्षेत्रों के बदलाव के साथ-साथ जीएसटी के कार्यान्वयन के चलते पिछले कुछ समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
- इन सबका असर औद्योगिक उत्पादन, निवेश, उपभोग और कारोबारी माहौल पर पड़ा, जो अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।
- इसके अलावा लम्बे समय से राज्यों का असमान आर्थिक विकास भी देश की अर्थव्यवस्था के लिये एक बड़ी चुनौती बना रहा है।

पहली चुनौती : देश में असमान आय वितरण

- पिछले वर्ष इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप ऑक्सफैम आवर्स द्वारा दुनिया में बढ़ रहे धन के समान वितरण के संबंध में रिवॉर्ड वर्क, नॉट वेल्थ नामक रिपोर्ट जारी की गई थी।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, गत वर्ष भारत में कुल धन का 73 प्रतिशत का केवल एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास था, जबकि देश की लगभग आधी आबादी (67 करोड़) की आय में मात्र एक प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है, जो कि निर्धन है।
- इतना ही नहीं देश की सबसे गरीब आबादी (3.7 करोड़) की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई।

दूसरी चुनौती : राजकोषीय संतुलन बनाना

- भारत में आर्थिक स्तर पर वित्तीय अनुशासन की कमी रही है, जबकि आर्थिक शक्ति बनने के लिये देश में आर्थिक अनुशासन का वातावरण अनिवार्य रूप से होना चाहिये।
- इस वित्तीय अनुशासनहीनता का ही दुष्परिणाम है राजकोषीय घाटा।
- बढ़ता राजकोषीय घाटा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि इससे ब्याज दरों के साथ-साथ मुद्रास्फीति दर (महँगाई) भी बढ़ती है।
- इसीलिये भारतीय परिस्थितियों के मद्देनजर अर्थशास्त्री राजकोषीय घाटे को कम-से-कम रखने पर जोर देते हैं।

तीसरी चुनौती : विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाना

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की संपत्ति हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये यह संपत्ति आम जनमानस के हाथों में होनी चाहिये, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों में जन-स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- इसके लिये सरकार इनमें विनिवेश का रास्ता चुनती है, जिससे उसके पास अतिरिक्त धन की उपलब्धता हो जाती है, जिसे सामाजिक योजनाओं और विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकता है।

चौथी चुनौती : बैंकों के बढ़ते एनपीए

- भारत की बैंकिंग प्रणाली ऐसी चुनौती भरी पृष्ठभूमि में अपेक्षाकृत लंबे समय से कार्य कर रही है जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता तथा लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- एनपीए का स्तर 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाने के कारण चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि किसी काम की नहीं है।
- यदि इस राशि की वसूली हो जाती है तो सरकारी बैंकों की लाभप्रदता में इजाफा, लाखों लोगों को रोजगार, नीतिगत दर में कटौती का लाभ कारोबारियों तक पहुँचना, आधारभूत संरचना का निर्माण, कृषि की बेहतरी, अर्थव्यवस्था को मजबूती, विकास को गति देना आदि संभव हो सकेगा।

पांचवीं चुनौती : कृषि क्षेत्र की चुनौती

- वर्तमान में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बहुत अधिक नहीं है, फिर भी कृषि उत्पादन में गिरावट विकास दर को निश्चित ही प्रभावित करती है।
- स्वतंत्रता के समय देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत था, जो अब घटकर केवल 14 प्रतिशत रह गया है।
- सर्वाधिक उत्पादकता वाले इस क्षेत्र पर देश की लगभग 58 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर करती है।
- घटी हुई विकास दर न केवल कृषि पर निर्भर देश के 14 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि आम आदमी भी महँगाई से परेशान हो जाता है।
- चूँकि देश की बहुत बड़ी आबादी रोजगार के लिये खेती-किसानी से जुड़ी हुई है, इसलिये कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट रोजगार संकट को भी बढ़ा देती है।

छठी चुनौती : रोजगार की चुनौती

- भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक बड़ी चुनौतियों में से एक है- रोजगार सृजन की चुनौती।
- इस समस्या के समाधान के लिये एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमारे देश में लगभग 13-15 लाख युवा प्रतिवर्ष कार्यशील जनसंख्या में तब्दील हो जाते हैं, जो रोजगार के उपयुक्त अवसरों की तलाश में रहते हैं।
- देश की लगभग आधी आबादी कृषि क्षेत्र में लगी है तथा वहाँ और अधिक लोगों को रोजगार दे पाना संभव नहीं है। अत: समय की मांग यही है कि गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उपाय किये जाएँ।

GS World टीम...

सातवीं चुनौती : कच्चे तेल के दाम

- देश में खाद्य उत्पादों की बढ़ती महँगाई के साथ इधर कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी होने से घरेलू बाजारों में तेल की कीमतें वर्तमान में सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गई हैं, जिसका विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- भारत भारी विदेशी मुद्रा खर्च कर अपनी जरूरत का लगभग 80 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है और ऐसे में इसके घरेलू दामों को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है।

आठवीं चुनौती : श्रम सुधारों की आवश्यकता

- हमारे देश में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बहुत अधिक श्रम कानून हैं, जो प्रायः औद्योगिक विकास में बाधक बनते हैं।
- यदि देश में अधिकाधिक रोजगारों का सृजन करना है तो सर्वप्रथम श्रम कानूनों के आधिक्य को कम करना होगा।
- कठोर श्रम कानूनों के कारण औद्योगिक प्रगति नहीं हो पाती, जो आगे चलकर रोजगारहीनता का एक बड़ा कारण बनती है।
- श्रम सुधारों को कारोबार से जोड़कर ही मानव संसाधन को उत्पादक संपत्ति बना पाना संभव हो पाएगा।
- इसके अलावा रोजगार सृजन के लिये अनुकूल माहौल बनाना भी बेहद आवश्यक है। इसके लिये जहाँ एक तरफ छोटे एवं मध्यम उद्यमों से बोझ घटाने की जरूरत है, वहीं इन सुधारों को कामगारों के लाभ से भी जोड़ना होगा।

नौवीं चुनौती : निजी (कॉर्पोरेट) निवेश

- केवल सरकारी निवेश से भारत जैसे लोक-कल्याणकारी देश में विकास को गति दे पाना लगभग असंभव है।
- अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये सरकार को प्रोत्साहन पैकेज के साथ-साथ निजी निवेश को बढ़ावा देने की खातिर पूंजी व्यय बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिये।
- वर्तमान में निजी निवेश गिरा है और वास्तविकता यह है कि पूंजी पर सार्वजनिक व्यय में बहुत कम वृद्धि हुई है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत का विकास भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 7.4% अनुमानित है।
   2. एनिमल स्पिरिट्स से तात्पर्य बाजार अर्थव्यवस्था में निवेशकों और उपभोक्ताओं के व्यवहार को निर्देशित करने वाली भावनाओं और प्रवृत्ति को संदर्भित करना है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: पिछले कुछ समय से विमुद्रीकरण, मौद्रिक नीति का नया ढाँचा असमान आय वितरण, बैंकों के बढ़ते एनपीए आदि ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया है? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

नोट : 3 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(c) होगा।